



Website:www.pratahkalexpress.in |

E-mail :pratahkalexpress@gmail.com |

facebook.com/pratahkalexpressnews |

https://twitter.com/ratahkalexpress1 |

एसीपी विवेक भगत को निशाना बनाने वाले फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली।(एजेंसी)

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 24 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार को कथित तौर पर एक फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इस वीडियो में हालिया प्रदर्शनों के दौरान एसीपी विवेक भगत को एक महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया था।

पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रसारित किया गया यह वीडियो छेड़छाड़ कर तैयार किया गया था और इसे फर्जी तरीके से



सीसीटीवी फुटेज के रूप में पेश किया गया। वीडियो के साथ भगत की तस्वीर, नाम और पद भी दिखाया गया था, जिससे यह आभास होता था कि वीडियो में दिखाई दे रहा पुलिस अधिकारी वही है।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि साइबर पुलिस का यह मामला भगत के खिलाफ एक महिला पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोपों से अलग है। महिला पत्रकार ने अधिकारी पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस शिकायत की जांच अपराध शाखा कर रही है।

जम्मू-कश्मीर से 150 बांग्लादेशी नागरिक निर्वासन के लिए IAF के विमान से भेजे गए

श्रीनगर।(एजेंसी)

जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशी नागरिकों को सोमवार को विमान से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा भेजा गया, जहां से उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ये 150 लोग उन करीब



500 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए चलाए गए सर्वेक्षण के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हिरासत में लिया गया था। इन सभी को पुलिस की निगरानी वाले एक केंद्र में रखा गया था।

अधिकारियों के अनुसार, बागडोगरा से इन 150 लोगों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस वर्ष मई में गठित जनसांख्यिकीय बदलावों संबंधी उच्चस्तरीय समिति के जम्मू-कश्मीर के पहले दौर के करीब दो महीने बाद सामने आया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि 150 प्रवासियों के इस जत्थे को भारतीय वायु सेना के एक विमान से भेजा गया। सूत्रों के अनुसार, उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सौंपा जाएगा और 7 अक्टूबर को बांग्लादेश निर्वासित किया जाएगा।

सिंगापुर के पूर्व मंत्री ने बताया, चीन की तुलना में भारत में विदेशी खुद को अधिक सहज क्यों महसूस करते हैं

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येओ ने कहा कि भारत की विविधता, भौगोलिक स्थिति और सभ्यतागत खुलेपन से उसे दुनिया में एक विशिष्ट बंदूत मिलती है। उन्होंने कहा कि इसके कारण विदेशी लोगों को भारत में अपनापन और सहजता का ऐसा अनुभव होता है, जो उन्हें चीन में शायद नहीं मिल पाता।

चंडीगढ़।(एजेंसी)

सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येओ ने कहा है कि भारत की विविधता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का लंबा इतिहास विदेशी लोगों को सहजता और अपनापन महसूस कराता है, जो उन्हें चीन में शायद



अनुभव न हो। येओ ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित पांचवें कोटिल्य आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति और सदियों से विभिन्न संस्कृतियों के साथ उसके संपर्क ने उसे बाहरी

बड़े फेरबदल के बाद यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के 8 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में

राज्यसभा के आठ

उम्मीदवारों के लिए

अंतिम दिन नामांकन

दाखिल किया।

समाजवादी पार्टी ने

संकेत दिया है कि वह

चुनावी मुकाबले से बच

सकती है, जिससे सभी

उम्मीदवारों के निर्विरोध

चुने जाने की संभावना

बन गई है।

लखनऊ।(एजेंसी)

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा के आठ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं, विपक्षी समाजवादी पार्टी ने संकेत दिया कि वह 16 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में मुकाबला नहीं करेगी। सपा के दो उम्मीदवार पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में 10 सीटों के लिए चुनाव अंतिम समय में कोई बदलाव नहीं होने पर बिना मतदान के संपन्न होता दिखाई दे रहा है।

भाजपा के सभी आठ उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर अजीत वर्मा के समक्ष नामांकन पत्र जमा किए। भाजपा द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलन दिखाई दिया है, जिसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

भाजपा उम्मीदवारों में ओबीसी समुदाय से धर्मपाल सिंह, प्रकाश पाल और श्रुति गंगवार; दलित समुदाय से विद्या सागर

सोनकर और प्रियंका रावत; तथा राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण

पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान शामिल हैं।

चुनाव अधिकारी अजीत वर्मा ने बताया, “सभी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के दो-दो सेट दाखिल किए हैं। प्रत्येक सेट के



साथ 10 विधायकों के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर थे।”

समाजवादी पार्टी के जिन दो उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन दाखिल किया है, उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी धनराज परिमल नाथवानी

कयास लगाए जा रहे थे कि सपा मुकाबला कराने के लिए तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नई दिल्ली खाना होने से पहले एक्स पर पोस्ट कर इस संस्पर्स

को खत्म करने का संकेत दिया। वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली खाना हुए थे।

यादव ने कहा, “अब हमारा ध्यान तीन पर नहीं, बल्कि 403 पर है।” भाजपा ने सपा के रुख पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “तस्वीर साफ है। सपा ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है।”

इससे पहले मंगलवार को भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा के सामने स्थित पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए। उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े सहित वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद वे डोल-नगाड़ों और जश्न के बीच नामांकन दाखिल करने के लिए खाना हुए।

महाराष्ट्र पुलिस ने सीजेपी स्वयंसेवकों से दिल्ली प्रदर्शन में शामिल न होने को कहा, पूछा- खर्च कौन उठा रहा है- दीपके

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले सीजेपी के संस्थापक ने चंद्रपुर पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को “तानाशाही” करार दिया। वहीं, जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन से पहले ऐसे नोटिस जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है।

मुंबई।(एजेंसी)

कॉक roach जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह आरोप चंद्रपुर पुलिस द्वारा उन स्वयंसेवकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद लगाया गया है, जो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। दीपके ने पुलिस की इस कार्रवाई को “तानाशाही” करार दिया।

चंद्रपुर के बल्लारपुर पुलिस थाने ने 5 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 168 के तहत सीजेपी के एक समर्थक को नोटिस जारी किया था। दीपके ने इस नोटिस को एक्स पर साझा किया। नोटिस में



कहा गया है कि पुलिस को जानकारी मिली है कि संबंधित व्यक्ति प्रस्तावित मार्च में दीपके का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली जाने की योजना बना रहा है।

नोटिस में उससे पूछा गया है कि वह सीजेपी के आंदोलन

मान के सहयोगी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया



सरकार के एक अधिकारी ने घटनाक्रम को पुष्टि करते हुए कहा, “हम याचिका के स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रहे हैं।” हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को ईडी द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भेजे गए पत्र में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने तथा दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

दिया था। यह मामला 7 दिसंबर को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है।

ईडी ने मान के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्नन और उनके कथित सहयोगियों नितिन गोहल तथा बीर देविंदर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।

ईडी ने क्या आरोप लगाए

ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 30 जुलाई को डीजीपी को भेजे अपने पत्र में आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसमें कथित तौर पर ऐसे सबूतों का हवाला दिया गया था, जिनसे धन के बदले तबादलों और नियुक्तियों, सरकारी नीतियों एवं निविदाओं पर प्रभाव डालने.

तमिलनाडु उपचुनाव में विजय की टीवीके की पहली बड़ी परीक्षा, अब तक मतदान में तेजी

पटना।(एजेंसी)

तमिलनाडु में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित मधुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान जारी रहा। मतदान तेजी से आगे बढ़ा और किसी बड़ी अप्रिय घटना या व्यापक तकनीकी खराबी की सूचना नहीं मिली। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा सुबह 11 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, मधुरंतकम में 35.55 प्रतिशत और धारापुरम में 37.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही अलग-अलग आयु वर्ग के



सत्तारूढ़ टीवीके की पहली चुनावी परीक्षा है। कुछ मतदान केंद्रों पर मामूली तकनीकी दिक्कतें सामने आईं। मॉक पोल के दौरान वीवीपैट या ईवीएम कनेक्शन से जुड़ी कुछ देर की देरी हुई, लेकिन तैनात इंजीनियरों ने इन्हें मतदान में तेजी आने से पहले ठीक कर दिया।

मधुरंतकम के थंडरई मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिए मतदान रोक दिया गया। डीएमके एजेंटों ने आरोप लगाया कि ईवीएम पर टीवीके उम्मीदवार के “सीटी” चुनाव चिह्न के बगल वाले बटन पर अमिट स्थाई के निशान लगाए गए थे, जिससे मतदाताओं के प्रभावित होने की आशंका थी। चुनाव अधिकारियों ने मशीन का निरीक्षण किया, समस्या का समाधान किया और मतदान फिर शुरू करा दिया। मधुरंतकम के बिल्वरायनहूर मतदान केंद्र पर डीएमके कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने सत्तारूढ़ टीवीके के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के अधिक करीब खड़े होने की अनुमति दी।

मंगलवार को मधुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मामूली स्थानीय बाधाओं के बीच मतदान तेजी से जारी रहा। मई में सत्ता में आने के बाद इन चुनावों को टीवीके की पहली चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।



कर भेजी गई दो खेप प्राप्त की थीं और उनके पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में होने का संदेह है। पुलिस ने मामले में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) तथा शस्त्र अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। मामले की आगे जांच जारी है।

पाकिस्तानी आतंकवादी के मारे जाने के कुछ दिन बाद हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के एक शीर्ष आतंकवादी को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के यूसमर्ग में सेना के एक ऊंचाई वाले इलाके में चलाए गए अभियान में मार गिराया गया था।

टीचर दंपति का कातिल निकला वैन ड्राइवर, चोरी करते पकड़ा तो मार डाला; ट्रांजेक्शन से खुली पोल

सुल्तानपुर के कादीपुर में शिक्षक दंपति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। स्कूल बस चालक राकेश यादव ने पट्टीदार आशीष संग चोरी करते पकड़े जाने पर फावड़े-कुल्हाड़ी से दंपति की हत्या की थी। हत्या के बाद शिक्षिका के मोबाइल से हुए 5 हजार रुपये के ट्रांजेक्शन से पुलिस को सुराग मिला।

एजेंसी
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के कादीपुर के कुम्ही डडिया गांव में शिक्षक दंपति की हत्या उनके ही स्कूल बस चालक राकेश यादव ने पट्टीदार संग चोरी करते पकड़े जाने पर फावड़े-कुल्हाड़ी से की थी। पुलिस को चकमा देने के लिए चालक ने अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर दोनों के शव मिलने की सूचना दी थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और पृछताछ में पुलिस को चालक पर शक हुआ। हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने वारदात कबूल ली। उसके निशानदेही पर पट्टीदार आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दोहरे हत्याकांड में शिक्षिका विनीता के मोबाइल से घटना के बाद हुए पांच हजार रुपये के ट्रांजेक्शन ने पुलिस को अहम सुराग दिया।

रुपयों के ट्रांजेक्शन से खुली पोल
पोस्टमार्टम में दंपति की मौत का समय रात करीब 12 बजे सामने आने के बाद पुलिस ने मोबाइल ट्रांजेक्शन की पड़ताल की। देर रात विनीता के मोबाइल से रुपये ट्रांसफर किए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस का शक गहराया। पूछताछ में बस चालक राकेश ने हत्या के बाद विनीता के मोबाइल से पांच हजार रुपये ट्रांसफर करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार उसे मोबाइल का पासवर्ड भी पता था। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद आरोपियों ने विनीता का मोबाइल कुएं में फेंक दिया था। पुलिस टीम मोबाइल और घटना में इस्तेमाल हथियार की तलाश कर रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 34,950 रुपये बरामद किए गए हैं।

आरोपी चोरी के इरादे से स्कूल परिसर में घुसे थे
एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि कुम्ही डडिया निवासी मुकेश सिंह परिषदीय विद्यालय में शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक संघ मोतिगपुर ब्लॉक अध्यक्ष थे। पत्नी विनीता कुम्ही डडिया में मनराजी शिक्षण संस्थान चलाती थीं। दोनों स्कूल परिसर में ही आवासीय मकान बनाकर रहते थे। 28-29 सितंबर की रात चालक राकेश यादव ने पट्टीदार आशीष उर्फ डब्बू के साथ चोरी के इरादे से स्कूल परिसर में प्रवेश किया था। विनीता ने दोनों को देख लिया तो पहचान उजागर होने के डर से राकेश ने उनकी हत्या कर दी। यह देखकर भाग रहे मुकेश को भी मार डाला।

पहचान होने पर किया आरोपियों ने हमला
पुलिस के मुताबिक राकेश अपने पट्टीदार आशीष यादव उर्फ डब्बू के साथ चोरी के इरादे से शिक्षक दंपति के घर में घुसा था। राकेश को घर में रुपये की तिजोरी के बारे में जानकारी थी। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर विनीता मौके पर पहुंचीं और दोनों को देख लिया। पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। शोर न मचा सकें, इसके लिए मौके पर पड़े फावड़े से उनके सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पत्नी पर हमला होते देख शिक्षक मुकेश कुमार सिंह जान बचाकर भागे।

CCTV भी पकड़ न पाए! विग लगाकर बाइक चोरी करता हिस्ट्रीशीटर, फिर उतार देता

बिजनौर के अफजलगढ़ में पुलिस ने विग लगाकर बाइक चोरी करने वाले हिस्ट्रीशीटर सोनू उर्फ सोहेल को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की बाइक और एक जली हुई बाइक बरामद हुई। आरोपी पहचान छिपाने के लिए नकली बालों की विग पहनकर वारदात करता था।

एजेंसी
बिजनौर। अपनी पहचान छिपाने के लिए विग लगाकर बाइक चोरी करने वाले हिस्ट्रीशीटर को बिजनौर की अफजलगढ़ पुलिस ने चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। इसके अलावा एक जली हुई बाइक भी मिली है। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी कृष्ण कुमार बिस्नोई ने बताया कि ग्राम मानियावाला निवासी विशाल ने चार अक्टूबर को अफजलगढ़ थाने में तहरीर देकर बताया था कि घर के बाहर खड़ी उसकी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने उसके अनुसार दर्ज कर जांच शुरू की। पांच अक्टूबर को सूचना पर सोनू उर्फ सोहेल निवासी डूडा कॉलोनी, अफजलगढ़ को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई। साथ ही एक काले रंग की बाइक भी मिली, जिसे पेट्रोल डालकर जलाया गया था।

विग लगाकर करता था वारदात
पृछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने दो दिन पहले नैनीताल के रामनगर से अपाचे बाइक चोरी की थी। इस बाइक से अन्य वारदात की ओर पहचान छिपाने के लिए चोरी में इस्तेमाल की गई इस बाइक को जला दिया था। इसके बाद चार अक्टूबर की रात उसने विशाल की बाइक चोरी की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत मुकदमे पहले से दर्ज बताए गए हैं। पुलिस अन्य मामलों में भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार पृछताछ में हिस्ट्रीशीटर सोहेल ने बताया कि वह पुलिस की नजरों से बचने के लिए नकली बालों की विग पहनकर वारदात करता था। घटना के बाद बिग उतार देता था।

चार साल से लापता चल रहा था हिस्ट्रीशीटर सोहेल
सीओ अफजलगढ़ आलोक कुमार ने बताया कि सोहेल अफजलगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। जिसकी हिस्ट्रीशीट नंबर 84 ए है। सोहेल पिछले चार साल से जिले से लापता चल रहा था। उस पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट सहित 11 मुकदमे दर्ज हैं।

स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन

एजेंसी
देहरादून। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी मंगलवार को पोरंड ग्राउंड में एकत्रित हुए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। कई बार मांग उठाने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार की उदासीनता के चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।



उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम की करवट; 11 तक येलो अलर्ट, आज कहां-कहां बारिश

उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। 11 अक्टूबर तक येलो अलर्ट है। आज देहरादून-नैनीताल समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है।

एजेंसी
देहरादून। मॉनसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने छह से 11 अक्टूबर तक उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच, सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं चलीं जबकि देहरादून समेत कई शहरों में बारिश और बूदाबांदी हुई। मंगलवार सुबह भी देहरादून के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम निदेशक डॉ.सीएस तोमर के अनुसार, छह से आठ अक्टूबर तक 4200 मिमीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के

साथ गर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि, अधिकांश मैदानी

मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने से



जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद नौ से 11 अक्टूबर के बीच करीब 3800

तापमान गिरने की संभावना है। सात जिलों में अलर्ट चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़,

बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। इनमें गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

इन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, छह-सात अक्टूबर को नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी व पौड़ी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर भी पड़ सकता है।

हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी महिला से रेप; अदालत ने पूछा- सजा पूरी होने के बाद भी क्यों नहीं छोड़ा

एजेंसी
झारखंड। झारखंड में हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में रखी गई बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म मामले में तीन सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज कर तीनों को निर्लंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से पेश सीलबंद रिपोर्ट में भी महिला से तीन पुलिसकर्मियों द्वारा दुष्कर्म का उल्लेख है। मामले की अपील सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। अदालत ने प्रार्थी से राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर मांग है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि महिला को बांग्लादेश भेजने के लिए वर्ष 2023 से ही विदेश मंत्रालय को पत्राचार किया जा रहा है। हालांकि, अब तक जवाब नहीं मिला है। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने को कहा। बता दें कि हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने



रिट याचिका में बताया कि लोहसिंघना थाने से संबंधित मामले में महिला कोर्ट से बरी होने के बावजूद महिला डिटेंशन सेंटर में पड़ी है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने डिटेंशन सेंटर में वर्ष 2020 से 2022 के बीच उससे दुष्कर्म किए जाने की बात कही थी। **2018 में दर्ज हुए थे दो मामले** सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया

उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर पेरंड ग्राउंड में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से जल्दी समाधान की अपील करते हुए बताया कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है।

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में बिहार से दो हिन्दू युवक गिरफ्तार, एक बेगूसराय का

एजेंसी
गुवाहाटी/पटना। भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं कथित तौर पर पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बिहार से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का दावा है कि दोनों पाकिस्तान के एक खुफिया ऑपरेटिव के संपर्क में थे और सुरक्षा बलों से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा कर रहे थे। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पूर्वी चंपारण के अभिषेक कुमार सिंह (31), बेगूसराय के रीतेश सिंह (39) को पकड़ा है। दोनों गुवाहाटी के सतगांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित एक किराये पर रह रहे थे। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न युवक की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। स्थानीय स्तर पर परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जारी बयान में कहा कि सुरक्षा संबंधी जानकारी पाक को मुहैया कराने के आरोप में सेना के जवान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने कहा कि सेना के सेवानिवृत्त जवान को अनुबंध के आधार पर भी फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर की गई। **दोनों आईएसआई को भेज रहे थे जानकारी** पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सेना की खुफिया इकाई (मिलिट्री इंटेलिजेंस) से मिले शुरूआती इनपुट के आधार पर की गई। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि अभिषेक कुमार सिंह कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल है और उसके संबंध एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से हैं।

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में बिहार से दो हिन्दू युवक गिरफ्तार, एक बेगूसराय का

जुटाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जारी बयान में कहा कि सुरक्षा संबंधी जानकारी पाक को मुहैया कराने के आरोप में सेना के जवान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने कहा कि सेना के सेवानिवृत्त जवान को अनुबंध के आधार पर भी फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर की गई।

सजा पूरी होने के बाद भी नहीं छोड़ा
सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर सवाल उठाए। अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि यदि महिला को वर्ष 2021 में विदेशी अधिनियम के मामले में तीन साल की सजा हुई थी तो सजा पूरी होने के बाद उसे बांग्लादेश क्यों नहीं भेजा गया? डिटेंशन सेंटर में रखने की जरूरत क्यों पड़ी।

केवाईसी नहीं कराने वाले हजारों एलपीजी गैस कनेक्शन सस्पेंड, नहीं हो सकेगी बुकिंग

एजेंसी
सुल्तानपुर। अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद गैस कंपनियों ने नए कनेक्शन पर रोक लगा दी है। इस बीच ईकेवाईसी नहीं कराने वाले हजारों उपभोक्ताओं का कनेक्शन सस्पेंड कर दिया गया है। इससे यह उपभोक्ता अब बुकिंग नहीं करा सकेंगे। ईकेवाईसी कराने के बाद ही उनकी बुकिंग होगी। इशर घरेलू उपभोक्ताओं की बुकिंग 25 दिन के अंतराल पर होने से गैस उपभोक्ताओं को कई माह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गैस कनेक्शन से वंचित और ईकेवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को जुगाड़ से 1800 रुपए में घरेलू सिलेंडर मिल पा रहा है। दुर्गापूजा-दशहरा में घरेलू गैस सिलेंडर की खपत बढ़ने से बैंकलाग बढ़ने से एक बार फिर एजेंसियों पर भीड़ बढ़ सकती है। यूपी के सुल्तानपुर में ईंधन की सुविधा के लिए विभिन्न कंपनियों की 48 गैस एजेंसियां संचालित हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से पांच लाख 59 हजार 521 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया है। इसमें आईओसीएल,एचपीसीएल, बीपीसीएल गैस कंपनी के कनेक्शन शामिल हैं। युद्ध के बाद गैस कंपनियों ने ईकेवाईसी को अनिवार्य कर दिया। बुकिंग के समय ओटीपी अनिवार्य करने से ईकेवाईसी करने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ लगने लगी। सितंबर महीने तक थी डेडलान नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। इससे 50 हजार से अधिक परिवार गैस कनेक्शन से वंचित रह गए हैं। ईकेवाई कराने के लिए सितम्बर माह तक समय दिया गया था। कंपनी की ओर से निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद दो अक्तूबर को ईकेवाईसी नहीं कराने वाले



उपभोक्ताओं का कनेक्शन सस्पेंड कर दिया गया। इससे 50 हजार ईकेवाईसी नही कराने वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग पर रोक लग गई है।

कंपनी ईकेवाईसी कराने के बाद बुकिंग पर लगाई गई रोक हटाएगी। सोमवार को सुबह 10 बजे सुल्तानपुर गैस एजेंसी की पड़ताल की गई। एजेंसी पर सात से आठ उपभोक्ता दिखाई दिए। इसमें ईकेवाईसी के उपभोक्ता भी शामिल थे। गैस एजेंसी के संचालक जियाउल हसनैन ने बताया कि ईकेवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के बुकिंग पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ईकेवाईसी कराने वाले लोगों की संख्या रोजाना चार से पांच रहती है। ईकेवाईसी न कराने वालों में विदेश और अन्य

शहर में रहने वाले ज्यादातर उपभोक्ताओं का नाम शामिल है। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि गैस कंपनियों की ओर से ईकेवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं का स्पष्ट आंकड़ा नहीं भेजा गया है।

25 दिन का अंतराल, तीन से चार दिन में डिलेवरी

खाड़ी युद्ध के बाद गैस बुकिंग के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। इस समय शहर और ग्रामीण क्षेत्र में गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन के अंतराल पर हो रही है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बुकिंग के तीसरे दिन और ग्रामीण क्षेत्र में बुकिंग के चौथे या पांचवें दिन सिलेंडर मिलता है।

केवाईसी नहीं कराने वाले हजारों एलपीजी गैस उपभोक्ताओं का कनेक्शन सस्पेंड कर दिया गया है। सभी को सितंबर तक केवाईसी कराने का मौका दिया गया था। इसके बाद भी काफी लोगों ने नहीं कराया। कनेक्शन सस्पेंड होने से अब बुकिंग नहीं हो सकेगी।

केवाईसी न कराने वालों को कामर्शियल सिलेंडर का भरोसा जिले में नया घरेलू कनेक्शन पर रोक लगी है। 40 हजार से अधिक परिवारों के पास कनेक्शन नहीं है। खाड़ी युद्ध के बाद उनके सामने समस्या हो गई है। ईकेवाईसी नहीं करा पाने वाले 50 हजार परिवारों की बुकिंग भी बंद हो गई। जिससे इन परिवारों को पांच किलोग्राम के सिलेंडर की गैस 806 रुपए में खरीदना होगा। इसके अलावा एचपी कंपनी की ओर से नया कनेक्शन के तहत 10 किलोग्राम गैस का प्लास्टिक बाड़ी का सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है।

राज्यपाल ने किया राष्ट्रीय संगोष्ठी नाड़ी विश्लेषण- 2026 का शुभारंभ

नाड़ी विश्लेषण, आयुर्वेद का विज्ञान और भारत का गौरव : राज्यपाल पटेल

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि नाड़ी विश्लेषण विज्ञान, भारत की समृद्ध चिकित्सकीय ज्ञान परंपरा है। यह विज्ञान के साथ भारतीय ज्ञान की गौरवशाली विरासत भी है। आधुनिक तकनीक और आयुष विज्ञान के साथ नाड़ी विश्लेषण को जोड़ना और विस्तारित करना स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत बनाने का मार्ग है। उन्होंने संगोष्ठी के आयोजन की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि «सबके लिए स्वास्थ्य» के लक्ष्य की पूर्ति में आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह स्वस्थ जीवनशैली और स्व-देखभाल को बढ़ावा देता है। नाड़ी विश्लेषण, कम खर्चीली, बिना किसी शारीरिक नुकसान की जाँच विधि है, जिसमें जटिल उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नाड़ी विश्लेषण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती, सुलभ और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा जन स्वास्थ्य को नया आयाम दे सकती है। राज्यपाल श्री पटेल मंगलवार को नाड़ी विश्लेषण - 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन, राष्ट्रीय आयुष मिशन और पं.

खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में नाड़ी परीक्षा की व्यवहारिक तकनीकों की खोज एवं निदान में नाड़ी का नैदानिक महत्व विषय पर किया गया था। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि आज दुनिया आयुर्वेद केहॉलिस्टिक विजन और जीवन दर्शन की ओर लौट रही है। आयुर्वेद आरोग्य का ऐसा विज्ञान है, जो रोग के उपचार से आगे बढ़कर स्वस्थ जीवन और वेलनेस को बढ़ावा देता है। इसके बहुउद्देश्यीय महत्व के कारण आयुर्वेद का भविष्य स्वर्णिम है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, हमें अनुशासन सिखाता है। मौसम के अनुसार खान-



पान और जीवन शैली में परिवर्तन का मार्गदर्शन देता है। आयुष की अलग-अलग विधाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। योग, हौम्योपैथी और नैचुरोपैथी हर घर-हर व्यक्ति तक पहुंच गई हैं। परिणामस्वरूप आज विश्वभर में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासित जीवनशैली और संयमित खान-पान की उपयोगिता बताई। सभी को नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, भरपूर नींद और पर्याप्त पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेद को नई पहचान दिलाई है। समय की मांग

है कि नाड़ी विश्लेषण के पारंपरिक ज्ञान से जुड़े दावों का आधुनिक वैज्ञानिक मानकों और शोध पद्धतियों के आधार पर विश्लेषण तथा सत्यापन किया जाए। नाड़ी विश्लेषण की व्यक्तिपरकता और विशिष्ट आकलन के अंतरों को कम करने पर चर्चा की जाए। आधुनिक वैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर प्रमाणित विश्लेषण द्वारा इसे एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा बनाने पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में जहाँ आधुनिक जाँच सुविधाएँ सीमित हैं, आयुष्मान् आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नाड़ी विश्लेषण विधि के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों तक स्वास्थ्य परामर्श तथा प्रारंभिक स्वास्थ्य आकलन में आयुर्वेद चिकित्सक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संभावनाओं को भी खोजा जाना चाहिए। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ भगवान धन्वतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उनका आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्री शोभित जैन ने पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने आयु वर्षनम् - सिकल सेल लघु पुस्तिका का लोकार्पण किया।

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं जनसुनवाई में 154 आवेदन प्राप्त हुए



प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम श्री सुमित पांडेय ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 154 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एएसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम श्री पांडेय ने

जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर सवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पहले दिन 1.12 करोड़ बच्चों एवं किशोरियों को दी गई कृमिनाशन खुराक

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day) के अंतर्गत 06 अक्टूबर 2026 को प्रदेशभर में कृमिनाशन गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रथम दिवस की अब तक प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टिंग के

के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोग के लिए नियमित कृमिनाशन महत्वपूर्ण है। अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं सहित विभिन्न सेवा प्रदायगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्र



अनुसार, प्रदेश में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1.12 करोड़ बच्चों एवं किशोरों तथा प्रजनन आयु वर्ग की लगभग 1 लाख महिलाओं को कृमिनाशन हेतु एल्बेंडजोल की निर्धारित खुराक दी गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का उद्देश्य बच्चों, किशोरों एवं लक्षित प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में आंतों के कृमि संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है। कृमि संक्रमण के कारण होने वाली पोषण संबंधी समस्याओं एवं एनीमिया के जोखिम को कम करने तथा बच्चों एवं किशोरों

हितग्राहियों को कृमिनाशन सेवाएं प्रदान की गईं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर दवा सेवन से वंचित रहे पात्र हितग्राहियों के लिए 09 अक्टूबर 2026 मॉप-अप राउंड आयोजित किया जाएगा। मॉप-अप राउंड के दौरान प्रथम दिवस पर अनुपस्थित अथवा किसी अन्य कारण से एल्बेंडजोल की खुराक नहीं ले सके पात्र बच्चों, किशोरों एवं लक्षित प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को कृमिनाशक दवा दी जाएगी, ताकि अभियान के अंतर्गत अधिकतम पात्र हितग्राहियों का कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री संजीव कुमार झा ने मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्वाचन सदन भोपाल से वचंउल बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में 7, 8 और 9 अक्टूबर को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान किसी भी मतदाता से फार्म 6 के अलावा घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। सभी जिला उप निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार करने के निर्देश दिए। श्री झा ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को



18 वर्ष की है गई, उनके भी फॉर्म लिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म जमा कराए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। श्री झा ने सभी

जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा की वे इस ऑनलाइन प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रचारित करें और युवा मतदाताओं को खास तौर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अब तक के कार्यों की समीक्षा भी की। इंदौर तथा विदिशा में अच्छी प्रगति के लिए सराहना की।

‘सेवा फर्सट-इनोवेशन चैलेंज’ में अधिकतम कराएँ पंजीयन

विद्यार्थियों, युवाओं, स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं को मिलेगा वास्तविक समस्याओं के समाधान का अवसर

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

सेवा संकल्प अभियान 2026 अन्तर्गत राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के मध्यप्रदेश चैप्टर में पंजीयन का कार्य मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। ःसेवा फर्सट इनोवेशन चैलेंज- में अधिक से अधिक पंजीयन करने के साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया को धरातल पर उतारने के लिए आज मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने की। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप , राज्यसभा सदस्य श्री रजनीश अग्रवाल, श्री राजेंद्र सिंह, श्री आनंद स्वरूप के साथ ही आयुक्त एमएसएमई श्री कुमार पुरुषोत्तम , आयुक्त तकनीकी शिक्षा अवधेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में ःसेवा फर्सट इनोवेशन चैलेंज- की रूपरेखा पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से प्रस्तुत की गई। मंत्री समूह ने इसके प्रॉपर क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से समिति गठन किए जाने संबंधी शासन स्तर पर प्रार्थमिक तौर पर अनुमोदन दिया। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन और संचालन के लिए शासन स्तर से



शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे। इस संबंध में एमएसएमई विभाग द्वारा शीघ्र ही एक प्रारूप तैयार किया जाकर मंत्री समूह के अध्यक्ष श्री शुक्ला को प्रस्तुत किया जाएगा। सेवा फर्सट इनोवेशन चैलेंज- का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इससे

विद्यार्थियों, युवाओं, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, किसानों, कारीगरों और जमीनी नवाचारकर्ताओं को शासकीय, औद्योगिक, सामाजिक एवं पर्यावरण से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए प्लेटफार्म मिलेगा। इनोवेशन चैलेंज के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, एमएसएमई सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग से जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं पंजीयन की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिभागियों को इस नवाचार मंच से जोड़ना है। चैलेंज में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी, युवा, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, किसान, कारीगर, स्वयं सहायता समूह तथा ग्रामीण एवं जनजातीय नवाचारकर्ता सहभागी बन सकेंगे। इसके साथ ही दृष्टि, हस्स और हब्डुघर से जुड़े समूहों को भी अभियान से जोड़ जा रहा है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, उद्योग, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यटन, हस्तशिल्प, आपदा प्रबंधन तथा महिला एवं युवा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के समाधान आमंत्रित किए जा रहे हैं।

वन अधिकार पट्टे से मजदूर से कृषक बना रूपबसंत आदिवासी

शासकीय योजनाओं ने बदली गरीब आदिवासी परिवार की जिंदगी, अब साहूकारों पर निर्भरता खत्म

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

कभी खेती करने के लिए भी साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। जमीन पर अपना अधिकार नहीं था, इसलिए बैंक से ऋण भी नहीं मिलता था। आज मेरे पास जमीन का पट्टा है, किसान क्रेडिट कार्ड है और शासन की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब मैं मजदूर नहीं, अपनी जमीन का मालिक बनकर खेती कर रहा हूँ। खेती के साथ मजदूरी कर वे परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। मिट्टी की दीवारों और कवेलू की छत वाले घर में परिवार रहता था। बारिश के दिनों में छत से पानी न टपके, इसके लिए कवेलू के ऊपर पन्नी डालकर गुजारा करना पड़ता था। शादी के बाद परिवार की

जिम्मेदारियां बढ़ी तो रूपबसंत ने भी उसी भूमि पर खेती करने के साथ मजदूरी शुरू कर दी। लेकिन जमीन का अधिकृत पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य सामग्री खरीदने के लिए उन्हें साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। सिंचाई के लिए खुद का बोर नहीं होने के कारण दूसरे किसानों से पानी लेना पड़ता था और फसल आने पर उसका भुगतान करना पड़ता था। बच्चों की स्कूल फीस, कपड़े और त्योहारों की जरूरतों के लिए भी कई बार साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। फसल आने के बाद ब्याज सहित कर्ज चुकाने में अधिकांश आमदनी चली जाती थी। नतीजा यह था कि खेती होने के बावजूद परिवार को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। रूपबसंत के जीवन में बदलाव तब आया, जब वर्ष 2019-20 में उन्हें जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित एमपी वनमित्र पोर्टल के बारे में जानकारी मिली। गांव के लोगों से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में जाकर योजना की जानकारी ली और ऑनलाइन आवेदन किया। पात्रता पूरी होने के बाद वर्ष 2020-21 में उन्हें 0.325200

हेक्टेयर कृषि भूमि का वन अधिकार पट्टा प्राप्त हुआ। पट्टा मिलने की खुशी को याद करते हुए रूपबसंत कहते हैं कि यह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। जिस भूमि पर उनका परिवार वर्षों से खेती करता आ रहा था, अब उस पर उन्हें कानूनी अधिकार मिल गया था। उनके शब्दों में, पट्टा मिलने के बाद मुझे लगा कि अब मैं मजदूर नहीं रहा, मैं भी अपनी जमीन का मालिक और कृषक बन गया हूँ। भूमि का पट्टा मिलने के बाद रूपबसंत ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए आवेदन किया। वर्ष 2025 में बैंक द्वारा उनका केसीसी बनाया गया। इसके बाद उन्हें कम ब्याज दर पर खेती की जरूरतों के लिए ऋण मिलने लगा। बीज और खाद की व्यवस्था आसान हुई तथा मवेशी खरीदने के लिए भी कृषि ऋण स्वीकृत हुआ। इसके साथ ही रूपबसंत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया, जिसके अंतर्गत उन्हें प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लिया है। कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अब उन्होंने कृषि यंत्र सन्धिडी योजना के तहत

ट्रैक्टर लेने की भी योजना बनाई है। बैंकिंग सुविधा से उन्हें व्यक्तिगत दुग्धटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिला है। आज रूपबसंत का परिवार पहले की तरह आर्थिक परेशानियों से जूझने के बजाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा मिल रही है। परिवार पक्का मकान बनवा रहा है। पहले के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध होने से साहूकारों पर निर्भरता काफी कम हुई है। रूपबसंत बताते हैं कि पहले कर्ज और ब्याज के कारण फसल से हुई आमदनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने से पहले ही खत्म हो जाती थी। अब खेती के लिए संस्थागत ऋण, बीमा और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने से खेती अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो गई है। इससे उनकी आय और कृषि उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिला है। रूपबसंत के लिए वन अधिकार पट्टा केवल जमीन का दस्तावेज नहीं, बल्कि उनके परिवार के बेहतर भविष्य का आधार बन गया है। वे कहते हैं- वन अधिकार पट्टे ने मेरे और मेरे परिवार का जीवन बदल दिया है। पहले हम खेती करने के बावजूद गरीब थे और साहूकारों पर निर्भर रहते थे। आज मेरे पास अपनी जमीन का अधिकार है।

करवा चौथ पर चेहरे के साथ हाथ-पैर भी चमेकेंगे, रोज नहाने से पहले लगाएं ये देसी उबटन



करवा चौथ को लेकर महिलाएं खरीदारी से लेकर त्वचा की देखभाल तक की तैयारियां पहले से शुरू कर देती हैं. चेहरे के साथ हाथ-पैर और पूरे शरीर की स्किन को चमकदार बनाने के लिए आप देसी उबटन बनाकर लगा सकती हैं.

करवा चौथ पर सिर्फ चेहरा ही चांद सा रोशन नहीं दिखना चाहिए, बल्कि हाथ-पैरों की त्वचा भी चमकदार हो तो पूरा लुक कमाल के लगेगा. अगर स्किन हेल्दी-साफ, टैनिंग फी रहेगी तो मेहंदी और महारव लगाने के बाद हाथ-पैर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे. हमें अपने फेस के साथ ही हमेशा अपनी पूरी बांडी की स्किन की देखभाल अच्छे से करना चाहिए. हालांकि ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है. अभी करवा चौथ में तकरीबन 24 दिन बाकी हैं. ऐसे में आप अगर अभी से एक नेचुरल उबटन रोजाना नहाने से पहले लगाती हैं तो हाथ-पैरों की स्किन भी निखर जाएगी.

करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026 दिन गुरुवार को किया जाएगा. इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करके शाम को चंद्र पूजन करती हैं. इस दौरान दुल्हन की तरह सोलह श्रृंगार किया जाता है और हर महिला चाहती है कि वो शादी की तरह बेहद खूबसूरत दिखे. ऐसे में त्वचा का हेल्दी और ग्लोइंग होना बहुत जरूरी है. निखार एक दिन में नहीं आता है. यहां बताया गया ये देसी उबटन रोज लगाएंगी तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है.

इंग्रेडिएंट्स कर लें नोट

सूखे हुए संतरा के छिलके का पाउडर, नींबू के छिलके का पाउडर, शुद्ध हल्दी पाउडर, बेसन या चावल का आटा, गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, चंदन पाउडर, एलोवेरा जेल, मुलेठी का पाउडर, दही या कच्चा दूध. अब जान लें उस उबटन को बनाने का तरीका.

उबटन का पाउडर करें तैयार

चंदन पाउडर, संतरा के छिलके का पाउडर, बेसन या चावल का आटा, चंदन पाउडर को बराबर मात्रा में मिला लें. जैसे मान लीजिए 2-2 चम्मच. इसमें आधी मात्रा में हल्दी पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, मुलेठी का पाउडर मिलाएं. सारी चीजों को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें.

कैसे बनाएं ये उबटन?

एक बाउल में तैयार किया गया पाउडर दो से तीन चम्मच निकाल लें ताकि इतनी मात्रा रहे कि ये पूरे शरीर पर अच्छे से अप्लाइ हो जाए. इसमें एलोवेरा जेल डालें. उसी के साथ दही भी मिलाएं. ये इतनी मात्रा में मिलाना है कि एक स्मूथ पेस्ट जैसा बनकर तैयार हो जाना चाहिए. बस तैयार है आपका टैनिंग, डेड स्किन हटाने वाला उबटन.

कैसे लगाएं इसे?

इस उबटन को आप नहाने से तकरीबन 20 मिनट पहले अप्लाइ करें. जब ये लगभग 75 प्रतिशत सूख जाए तो हाथों में पानी या फिर गुलाब जल लेकर इसे स्किन पर थपथपा लें. इसके बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए उबटन को क्लीन कर लें. ये न सिर्फ आपकी स्किन को चमकाएगा, बल्कि मुलायम भी बनाएगा और गहराई से साफ भी करेगा. हाथ-पैरों और पूरे शरीर की त्वचा के साथ ही इसे आप अपने फेस, गर्दन पर भी अप्लाइ कर सकती हैं.

नोट: इस उबटन में वैसे तो सारी चीजें ही नेचुरल हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको एक बार इसका पैक टेस्ट जरूर करना चाहिए. थोड़ा सा उबटन लेकर इसे कान के पीछे या फिर कोहनी पर लगाकर छोड़ दें. इसके कुछ घंटे के बाद देखें किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हो रही है.

भारत में नया राजनीतिक आख्यान-'प्रधानमंत्री मोदी के मोहरे हैं ज्ञानेश कुमार'

चुनावी आख्यान में बदलाव साफ़ दिख रहा है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले अहम राज्य चुनावों से ठीक पहले वोट चोरी का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता है। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े की भी मांग की है। इंडिया ब्लॉक ने इस आंदोलन को न सिर्फ़ 'सड़कों पर, बल्कि संसद और अदालतों तक भी ले जाने की योजना बनाई है।

विपक्षी इंडिया गठबंधन का नया राजनीतिक आख्यान यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहरें हैं, जिनके ज़रिए भारत के चुनावी लोकतंत्र को अगुवा कर लिया गया है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा सीईसी ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के निशाने पर हैं। 2 अक्टूबर से सीईसी के विरोध में आंदोलन तेज़ हो गया है, जो पूरे हफ़्ते यानी 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों, खासकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में सीईसी और मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ़ कई मामलों की सुनवाई होगी।इसके साथ ही, सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए 2023 के अधिनियम से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक जज ने बंटा हुआ फैसला दिया था, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कानून के तहत सीईसी को उनकी नियुक्ति के मामले में भी मदद मिली। आरोप है कि जज का बंटा सीईसी के वकीलों के पैलल में शामिल हैं। मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि उसी जज ने हाल ही में सीईसी ज्ञानेश कुमार की बेटी और नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम को राहत देते हुए एक फ़ैसला सुनाया था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई सख़्त टिप्पणियों और 5 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने नोएडा में मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान शामिल एक छात्रा एक्टिविस्ट को एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के मामले को रद्द कर दिया था।हालांकि आम धारणा यह है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार अब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अपने और अपने निर्णयों से जुड़े मामलों को सफलतापूर्वक संभालते रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जब इन मामलों की सुनवाई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कई फैसलों को बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने भी गैर-कानूनी% और %बिना अधिकार के लिए गए फैसले% बताया था, जबकि उन्होंने अपने फैसलों को ईसीआई के सर्वसम्मत फ़ैसले के तौर पर पेश किया था। 2 अक्टूबर के बाद जब सीईसी के खिलाफ़



आंदोलन तेज़ हो गयी है, तो इसकी गुंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इसमें न सिर्फ़ इंडिया ब्लॉक की पार्टियां, बल्कि %कॉकरोच जनता पार्टी% (सीजेपी) के बैनर तले जेन जी, सिविल सोसाइटी और आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।सीईसी के खिलाफ़ यह आंदोलन, जो असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता है, अब एक नए और मजबूत चरण में प्रवेश कर रहा है। इस हफ़्ते 2 से 8 अक्टूबर तक देशव्यापी %लोकतंत्र बचाओ% विरोध प्रदर्शन होंगे, 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद ईसीआई तक मार्च करेंगे, सीजेपी ने 2 अक्टूबर से %जेल भरो% आंदोलन और प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और देश के सभी ज़िलों में कई अन्य विरोध रैलियां होंगी। चूँकि यह सीईसी के खिलाफ़ एक संयुक्त अभियान होगा जो असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ है- इसलिए यह अब तक के ऐसे किसी भी आंदोलन से ज्यादा मजबूत होगा। चुनावी आख्यान में बदलाव साफ़ दिख रहा है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले अहम राज्य चुनावों से ठीक पहले वोट चोरी का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता है। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े की भी मांग की है। इंडिया ब्लॉक ने इस आंदोलन को न सिर्फ़ 'सड़कों पर, बल्कि संसद और अदालतों तक भी ले जाने की योजना बनाई है।

वे सीईसी और अन्य ईसी नियुक्ति अधिनियम 2023 की धारा 16 को भी चुनौती देने की योजना बना रहे हैं, जो सीईसी को मुकदमों या उनके खिलाफ़ कार्रवाई से आजीवन सुरक्षा देती है।

यह हफ़्ता सीईसी ज्ञानेश कुमार के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि उन्हें ईसीआई के भीतर संस्थागत अलगाव महसूस हो रहा है। वहां दो चुनाव आयुक्त उनके सभी फ़ैसलों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, खासकर उन फ़ैसलों का जो गैर-कानूनी और अनधिकृत हैं। विश्वसनीयता खोने के कारण, उन्हें आयोग के भीतर, न्यायपालिका में और देश भर में राजनीतिक स्तर पर मामलों से निपटने में मुश्किल होगी। उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के कामों की जांच न्यायपालिका, राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी और उन सभी लोगों द्वारा की जाएगी जो देश के चुनावी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं।इसलिए, सीईसी के लिए सबसे बड़ी समस्या जरूरी नहीं कि विरोध प्रदर्शन ही हों। अब यह साबित करने की जरूरत बढ़ती जा रही है कि आयोग के फैसले स्वतंत्र जांच, अंदरूनी असहमति, न्यायिक जांच और जनता की नज़र में खरे उतर सकते हैं। इतिहास

इन सभी बातों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत महत्व है, क्योंकि ईसीआई, सीईसी, और एसआईआर से जुड़ी राजनीतिक कहानी अब उनके

संपादकीय

एसआईआर के विरोध में चौतरफा आंदोलन

राहुल गांधी ने चार महीने पहले मई में कहा था कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। तब उनके बयान का खूब मजाक भाजपा ने बनाया था, क्योंकि उस समय भाजपा ने बंगाल, असम चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन राहुल गांधी ये कहते रहे कि उन्हें सिस्टम के अंदर से खबरें मिल रही हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। फिर 30 सितंबर को भी राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जल्द देश में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। एक बार फिर राहुल की बात पर भाजपा ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई और पूरे देश में जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध जनता दिखा रही है, उसके बाद राहुल गांधी की बात ही सच होती दिख रही है। एसआईआर के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार को बचाने की जितनी कोशिश नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं, उतना ज्यादा उनकी सरकार के गिरने का खतरा बढ़ रहा है।इंडिया गठबंधन ने 30 सितंबर की बैठक में ऐलान किया था

कि देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर मोर्चा खोला जाएगा, इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मुंबई में 2 अक्टूबर को प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर से फिर से जंतर-मंतर पर बैठने की चेतावनी दी है, अभिजित दिपके ने तो साफ कहा है कि पुलिस उन्हें जहां रोकेगी, वहीं जंतर-मंतर बन जाएगा। इधर नागरिक समाज की तरफ से भी मोदी सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो चुका है। शुक्रवार को गांधी जयंती पर नेहा बोरा, योगेन्द्र यादव, मनोज झा, संजय सिंह जैसे तमाम लोगों को पुलिस ने रोका, घसीटा, हाथों से उन पर वार किया, लेकिन उन्हें और उनके साथ खड़े हो चुके युवाओं को पुलिस नहीं रोक पाई। शनिवार को फिर जंतर-मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने मिला।2024 से पहले का वक़ होता तो ऐसी चुनौतियों को मोदी-शाह हवा में उड़ा सकते थे, लेकिन इस बार मामला संगीन हो गया है। एक के बाद एक आंदोलन, धरने और प्रदर्शन चल ही रहे हैं। यह सब

राहत दे रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जनता ही उठ खड़ी हुई है। ज्ञानेश कुमार के कारण चुनाव आयोग की साख़ तो पूरी तरह मिट्टी में मिल ही चुकी है, खुद उनकी अपनी साख़ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। अब से पहले कभी देश में चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गद्दार, चोर, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप कई बार लगे, विरोधी पार्टियों ने दबंगई करने, बूथ कब्ज़ा करने जैसे गंभीर आरोप भी एक दूसरे पर लगाए, लेकिन आरोपों का कीचड़ चुनाव आयोग पर कभी नहीं उछला। लेकिन मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार ने तो खुद को कीचड़ में सना दिया है। अब जनता जब इस कॉलिख पर ऊंगली उठा रही है तो चुनाव आयोग अपने फैसलों को पलट रहा है, मगर अब देर हो चुकी है।पूरे देश में एसआईआर रोकने की मांग तेज हो चुकी है और अपना वोट कटने से नाराज लाखों लोग सड़कों पर

उतर गए हैं तो अब चुनाव आयोग अपने फैसलों को पलट रहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में छूट गए लोगों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं या युवा मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। यानी पहले नाम काटे गए और अब जुड़वाने की कवायद आयोग करवा रहा है। इधर दिल्ली में चुनाव आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ के लिए ईसीआईनेट पोर्टल में कुछ नए विकल्प जोड़े हैं। इन विकल्पों के बाद अब ईआरओ किसी नोटिस पाने वाले मतदाता को बिना दस्तावेज जमा कराए और कुछ मामलों में बिना सुनवाई तय किए भी अंतिम मतदाता सूची के लिए योग्य घोषित कर सकते हैं। पहले किसी नोटिस के बाद मतदाता को दस्तावेज जमा करने और सुनवाई की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन इस पर काफी विवाद उठा था, तो अब आयोग ने फिर पलटी मारी है।

जनता को अब बंटना नहीं है, जंतर-मंतर से आई एकता को बनाए रखना है

बांटने की कोशिशें और हो सकती हैं। धर्म तो इनका आधार था ही। ाति के आधार पर। स्त्री-पुरुष के आधार पर। गांव-शहर किसी भी आधार र यह लोगों को बांटने की फिर कोई कोशिश कर सकते हैं। वही इनका ख़ियरी हथियार है। जनता को बस बंटने से होशियार रहना है। इन गान्दोलनों से आई एकता की शक्ति को बनाए रखना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश को हिन्दू-मुस्लिम में बांटा था। और अब न्होंने ही न केवल हिन्दू-मुस्लिम को बल्कि बाकी जाति और अन्य दूसरे वतने भी आधारों पर जनता को बांटा था सबको फिर एक कर दिया।। ठक सोच रहे होंगे यह हमने मोदी द्वारा जनता को एक करने की बात न्स आधार पर लिखी? उनका सोचना सही है। मोदी द्वारा बांटते हुए न्होंने देखा है। लेकिन यह वापस जनता के जुड़ने की बात?जी हां! हम ह इस आधार पर कह रहे हैं कि जन्तर मन्तर-2 शुरू होने के बाद भी ।ंदी जन्तर मन्तर -1 से सबक नहीं ले पा रहे हैं। उस आन्दोलन में शिक्षा ः मुद्दे पर सब एक हो गए थे। शिक्षा सबकी जरूरत है। और उसमें ंधर्धिलियां धर्म और जाति, छत्र और छत्राओं सबको प्रभावित कर रही थीं। टूटेंट की मांग इसके लिए दोषी शिक्षा मंत्री को हटाने की थी। और उसने ँबको एक कर दिया था। और आखिर एक महीने से ज्यादा समय तक रकार विरोधी माहौल सहने के बाद मोदी को अपने शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र धान का इस्तीफा लेना पड़ा था।मोदी ने उसमें जितनी देर की उतना ही नके खिलाफ माहौल बना। और अब वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ुमार को बचाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही उनके खिलाफ माहौल रैर बनेगा एवं जनता में एकता और बढ़ेगी। चुनाव में धांधलियां तो धर्म ाति, स्त्री पुरूष से आगे जाकर अमीर-गरीब, गांव, शहर सब जगह ावित कर रही हैं। इसी के खिलाफ जन्तर मन्तर-दो हो रहा है। अगर ।ंदी ने इसमें भी उतनी ही देर कर दी जितनी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे में की ी तो इस बार जनता की एकता फिर 2014 से पहले वाले पुराने स्तर पर हुंच जाएगी। और इस्तीफा तब भी उन्हें ज्ञानेश कुमार का लेना होगा।हम सतिए लिख रहे हैं कि मोदी ने ही बांटा था मोदी ही एक कर रहे हैं। आज ंसमझ नहीं पा रहे कि क्या करें? और फिर जब करने को कुछ नहीं रहता । वही करते हैं जो पहले करना था।जन्तर मन्तर का आन्दोलन बढ़ता जा ङ है और उसे दबाने के लिए सरकार पुलिस से ज्यादा ज्यादातियां करवा ी है। इस बार निशाने पर पत्रकार भी हैं। उन्हें काम करने से रोका जा ङ है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि महिला पत्रकारों के साथ पुलिस



द्वारा शारीरिक छेड़छाड़ की घंटिया हकत की जा रही है। एक महिला पत्रकार ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर पत्रकार संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।सरकार पुलिस के द्वारा जितना दमन करने की कोशिश करेगी जनता की एकजुटता उतनी ही बढ़ेगी। युवाओं के माता-पिता भी आन्दोलन में आएंगे। लोगों को बांटने की सारी कोशिशें असफल हो जाएंगी। और यही मोदी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी।वे बांटो और राज करो के आधार पर ही अब तक चुनाव जीत रहे थे। इसमें चुनाव आयोग उनका सबसे बड़ा सहयोगी था। अब दोनों चीजें टूट रही हैं। लोगों का बंटना बंद हो गया है और चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खुल जाने के बाद वह हिम्मत हार गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होना है। इसे कोई नहीं रोक सकता। मोदी देर चाहें जितनी कर सकते हैं। मगर इसमें उन्हें एक और खतरा है और वह बहुत बड़ा है। अपने खिलाफ आन्दोलन से घबरा कर कहीं ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी की बात न मान लें। ज्ञानेश कुमार यह तो समझ ही गए

इसी अहंकार में उन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस कर दीं। लेकिन हर चीज का एक समय होता है और वह दिखने लगा। शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह खत्म करने के कारण हुआ छत्र आन्दोलन एक बड़ा अभियान बन गया। और लगातार 37 दिन के आन्दोलन के बाद मोदी को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा था। उससे शुरुआत हो गई। और अब चुनाव आयोग के मामले में उससे भी तेज आन्दोलन शुरू हो गया। नया नेतृत्व उभर कर सामने आ गया। जेएनयू की नेहा बोरा एक ऐसी हिम्मती लड़की के तौर पर सामने आईं जो हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गईं।मोदी ने आन्दोलन के खिलाफ आंदोलनजीवी कहकर, जेएनयू के खिलाफ तो 2014 में सरकार बनने के साथ ही पहला निशाना उसी पर लगाकर, और अरबन नक्सल से लेकर नाराज फूफा तक पता नहीं जाने क्या क्या कहा। उद्देश्य था आवाजों को दबाना। मगर आवाजें कभी दबी हैं? वह तो राजशाही से लेकर अंग्रेजों के दौर तक हमेशा उठती रही है और अब लोकतंत्र में तो इसके दबने का सवाल ही नहीं।

हिन्दू-मुस्लिम की नफरती राजनीति ने कुछ समय के लिए विभाजन की आवाजों को तेज करके जनता की वास्तविक आवाजों को दबा दिया था। मगर इस नई पीढ़ी के आने के बाद हर वर्ग की आवाजें तेज उठने लगीं। इसी में नया नेतृत्व निकला है। मोदी के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है कि वह युवा पीढ़ी, छत्र-छत्राओं से मुठभेड़ का रास्ता छोड़कर उनकी समस्याएं सुलझाने का काम करें। धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा बहुत देर से लिया था। ज्ञानेश कुमार का जल्दी लें। चुनाव में धांधली से नहीं अपने कामों से वोट लें। समय अब उनके विपरीत आ गया है। ऐसे में आन्दोलनकारियों के साथ मिलकर बात करने में ही भलाई है।नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आन्दोलन को सत्याग्रह का नाम देकर व्यापक स्वरूप दे दिया है। आंदोलन सिर्फ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही नहीं उन्होंने देश में चल रहे हर आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।जनता की शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता। इतने समय तक लोगों को बांटकर जो सरकार चलाई है वह अब लोगों के एक होने से खतरे में आ गई है। यह जनता की ताकत है और लोगों के एक होने से आई है। बांटने की कोशिशें और हो सकती हैं। धर्म तो इनका आधार था ही। जाति के आधार पर। स्त्री पुरुष के आधार पर। गांव शहर किसी भी आधार पर यह लोगों को बांटने की फिर कोई कोशिश कर सकते हैं। वही इनका आखिरी हथियार है। जनता को बस बंटने से होशियार रहना है।